बिजली की जितनी आवश्यकता है वह तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि आप इसमे प्राईवेट सैक्टर को इन्वाल्य नही करेंगे । नौंवी पंचवर्षीय योजना में प्राईवेट सैक्टर के जरिए से 17586 मेगावाट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य था। लेकिन आपका जो कुल जेनरेशन हुआ है वह 5061 मेगावाट हुआ है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में आपने क्या लक्ष्य रखा है? 90 क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी जानकारी देगें ?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने प्राईवेट पावर प्रोजेक्ट के बारे में चिंता जताई है और वह सत्य है। नांइथ प्लान में हमारा 17000 मेगावाट का लक्ष्य था, लेकिन हम केवल 5000 मेगावाट का ही लक्ष्य पूरा कर पाये हैं । टैंथ प्लान में इसे देखते हुए 41000 मेगावाट का ल्क्ष्य तय किया है और उसमें प्राईवेट सैक्टर से केवल 7000 मेगावाट का टारगेट हमने तय किया है।

SHRIMATI PREMA CARIAPPA : Sir, during April-December, 2002, Rajasthan faced a power shortage of 81 per cent, Madhya Pradesh 14 per cent, Maharashtra 13 per cent and Karnataka 11 per cent. I would like to know from the hon. Minister whether the Government proposes to link the eastern region, which has surplus capacity, with the northern and southern regions, which are facing power shortage.

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, ईस्टर्न रीजन में जो सरप्लस बिजली है उसे सदर्न रीजन के लिए ले जाने के लिए आलरेडी तालचर से कोलार ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई है। लगभग सात सौ मेगावाट बिजली आज हम ईस्टन रीजन से सदर्न रीजन में ले जा रहे हैं । कोलार से सदर्न रीजन के जो चारों स्टेट्स हैं वहां से उनको बिजली दी जाती है।

Criminal cases against IAS/IPS Officers

*643. SHRI SWARAJ KAUSHAL : Will the Minister of PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS be pleased to state:

(a) the number of IAS and IPS officers against whom criminal cases are pending. State-wise;

(b) the number of IAS and IPS officers in jail in each State;

(c) the number of IAS and IPS officers on bail; and

(d) the State-wise list of IAS and IPS officers absconding?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRI HARIN PATHAK) :

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House on the basis of information received from the State Governments, Central Bureau of Investigation and as available with the Central Government.

Statement

State/Cadre	No. of officers involved in criminal cases		No. of officers in Jail		No. of officers on bail		No. of officers absconding	
	IAS	IPS	IAS	IPS	IAS	EPS	IAS	IPS
AGMUT	9	2	1	Nil	2	Nil	Nil	Nil
Andhra Pradesh	3	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Assam-Meghalaya	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Bihar	5	8	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Chhattisgarh	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Gujarat	3	10	Nil	Nil	Nil	2	Nil	Nil
Haryana	4	7	2	2	2	3	Nil	Nil
Himachal Pradesh	1	1	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Jharkhand	10	1	Nil	Nil	2	Nil	Nil	Nil
J&K	2	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Kamataka	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Kerala	8	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Madhya Pradesh	5	2	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Maharashtra	5	2	Nil	.Nil	Nil	2	Nil	Nil
Manipur-Tripura	1	ı	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Orissa	3	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Punjab	3	3	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Rajasthan	2	Nil	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
Silddm	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Tamil Nadu	9	10	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Uttar Pradesh	9	6	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
Uttaranchal	1	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
West Bengal	1	5	Nil	Nil	1	Nil	Nil	Nil
TOTAL	93	64	3	2	12	7	Nil	Nil

SHRI SWARAJ KAUSHAL: Sir, I find from the statement of the Minister that 157 IAS and IPS officers are involved in criminal cases. May I know from the hon. Minister out of these IAS and IPS officers, how many IAS and EPS officers have been given a posting and how many of them are actually working?

SHRI HARIN PATHAK: Sir, the procedure is very clear. As per rule 3(2) of the All India Services Rules, if an officer is arrested and kept in custody for more than 48 hours, he shall be deemed to be suspended. जो सस्पेंडिड हैं, उनको नौकरी में लेने का सवाल नही हैं । जो जेल में हैं ,उन्हें नौकरी पर लेने का सवाल नहीं हैं। इन्वेस्टीगेशन का स्टेज आता है।before aresting an officer and prosecuting him and then any imprisonment is given to him by the court. इन्वेस्टीगेशन स्टेज पर किसी अधिकारी को राज्य ने नौकरी पर लिया है या नहीं लिया है....। उसके आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि राज्य से संबंधित पूरा विषय है। जो केन्द्र सरकार से है, उसके लिए तीन आईएएस अफसर और दो आईपीएस , जैसा मैंने कहा जेल में हैं और सस्पेंशन में हैं ।

श्री स्वराज कौशल : महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि इसमें से जो 152 अधिकारी हैं,या जो कुल 157 अधिकारी हैं, उनमें से कितने करप्शन के लिए प्रोसीक्यूट हो रहे हैं, कितने मर्डर केसिज़ हैं, उसका सीरियस ओफैंसिज़ के अनुसार क्लासीफिकेशन क्या हैं ?

श्री सभापति : अगर है तो बता दीजिएगा ।

उपप्रधान मंत्री , गृह मंत्रालय तथा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभारी श्री लाल कृष्ण आडवाणीः महोदय , ये जितन सारे केसिज करप्शन के हैं, मैजोरिटी जो है,ओवरवैल्मिग करप्शन के केसिज हैं। जिसको क्रिमिनल कह सकते हैं,जो ओवर ऑल फिगर है, वह यह है The percentage of officers involved in criminal charges comes to about 1.75 per cent. The rest are all under charges of corruption, बाकी कुछ मर्डर वगैरह के भी केसिज हैं वह जो हैं, It is a small percentage.

श्री राजनाथ सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो सारे पैंडिंग केसिज हैं, इन पैडिंग केसिज को ऐक्सपेडाइट करने के लिए और दूसरे केसिज के स्पीडी डिसपोजल के लिए क्या सरकार की तरफ से कुछ कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरिन पाठक : महोदय , विनीत नारायण के केस के जजमेंट के बाद यह तय किया गया है कि जितने भी केसिज पैंडिंग है जिनमें Approval for sanction for prosecution is required. तीन महीने के अंदर अदंर विभिन्न मंत्रालयों को, विभिन्न विभागों को उन्हें अप्रूवल फार सैंक्शन फॉर प्रासीक्यूशन देना चाहिए । जहां पर कानूनी सलाह की आवश्यकता हो, वहां पर एक महीना और, यानी ज्यादा से ज्यादा चार महीने के अंदर प्रासीक्यूशन सैंक्शन की सारी फारमैलिटीज

कम्पलीट करनी होती है । उसके साथ-साथ पीएमओ , कैबीनेट सैक्रेटरिएट , मिनिस्टरी परसोनल, सीबीआई-ये सारी संस्थाएं रैग्यूलरली इस पर मानिटरिंग करती रहती है, रिव्यू करती रहती है । 20 फरवरी , 2003 को कैबिनेट सैक्रटरी के यहां एक मीटिंग की गयी जिसमें करीब 106 केसिज ऐसे थे जो उन्होनें क्लीयर किए जिनका बाद में 31 मार्च को राज्यों में डिसपोज़ल हुआ । यह पूरी प्रक्रिया है जिस के अतंर्गत for monitoring and reviewing, the maximum time limit is three months. If legal advice is required, then one more month is given to them.

श्री रमा शंकर कौशिक : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि केवल तीन अधिकारी हैं जो केन्द्र से संबंधित हैं । उनकी पोस्टिंग के संबधं में उन्होनें जानकारी दी । महोदय,मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न के साथ सभी सूबों से जो वस्तुस्थिति है, उसका पता लगा लेना चाहिए था । काफी समय से यह प्रश्न पड़ा हुआ था, उस प्रश्न का जवाब आ सकता था । महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी आपराधिक मामले हैं, ये कितने साल पूराने मामले हैं , कृपया यह बताएं और कितने मामलों मे क्या-क्या प्रगति प्रॉसीक्यूशन के मामले में हो रही है ।

श्री हरिन पाठक : महोदय , जैसा मैने बतया कि 186 मामले अभी लम्बित हैं और आईएएस में 84 मामले ऐसे हैं जो करप्शन से संबंधित हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक : कितने समय से पैडिंग हैं ।

श्री हरिन पाठक : मैंने अपने उत्तर में शुरूआत में कहा है कि We have to collect the information from the CBI, from the State Governments about all these cases; regarding their investigations, prosecutions and punishment. *(Interruptions....)* I will collect the information.

श्री सभापित : इस समय आपके पास इनफार्मेशन नहीं हैं ।

श्री हरिन पाठक : मैं यह सब कलैक्ट करके उन्हें दे दुंगा । (व्यवधान)

श्री प्रेम गुप्ता : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है । (व्यवधान)

श्री सभापति : देखिए, आज आप इनकी जगह होते और यही प्रश्न आपसे करते तो जवाब वही मिलता ।...(व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता : महोदय , हम जवाब का नही । (व्यवधान)

श्री सभापति : गुप्ता जी, एक मिनट आप बैठ जाइए । मंत्री जी, आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए । आपने कहा कि कोई absconding नही हैं । Are you sure?

श्री हरिन पाठक : जो जवाब मेरे पास है, उसमें जब तक कोर्ट उसको absconding जाहिर नही करता तब तक उसको absconding नही माना जाता है । आज मेरे पास जो इनफॉर्मेशन हैं, जो राज्यो और केन्द्र से मिली है, उसमें कोई absconding नही हैं । (व्यवधान)

श्री प्रेम गुप्ता : मान्यवर, इस पर आधे धंटे का डिसकशन करा लीजिए ।

श्री सभापति सुन लीजिए –(व्यवधान)- आप नियम जानते है। आधे धंटे के डिसकशन

के लिए मैं इस समय फ़ैसला नही दे सकता। (व्यवधान) –यह गलत बात है। (व्यवधान)...

श्री प्रेम गुप्ता : आज कितने आई.ए.एस.और.आई.पी. एस. ...(व्यवधान)...

श्री सभापति **:** मैं एक बात बताऊं आपको । आप तो नियम जानते हैं। आधे घंटे का डिसकशन करने के लिए नियम बने हूए हैं । आप नियमों के तहत मुझे नोटिस दे दीजिए , मैं विचार करूंगा । ..(व्यवधान)..

श्री संजय निरूपम : सभापति जी, मुझे आधा घंटा नहीं,केवल आधा मिनट चाहिए ।

श्री लालू प्रसाद : सर, बिजनेस एडवाज़री कमेटी में हम डिसकस कर लेंगे । (व्यवधान)

श्री सभापति: आप पहले उस रूल के अतंर्गत मुझे नोटिस भेज दीजिए । (व्यवधान)

श्री संजय निरूपम **:** सभापति जी, मेरे सामने एक छोटा सा प्रश्न है।

श्री सभापति **:** मैं एलाऊ नहीं करूगां, किसी को एलाऊ नही करूंगा , बिलकुल नहीं ।

∗644. [The questioners (Shri Ram Jethmalani, Shri Kapil Sibal) were absent. For answer *vide* page ...*35....infra]*.

∗645. [The questioner (Shri Anil Sharma) was absent. For answer *vide* page... 36... *infra]*.

Suggestions of Members of Rajya Sabha in PMGSY

∗SHRI H.K. JAVARE GOWDA : Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) details of the new guidelines for roads under PMGSY schemes;

(b) whether, the Rajya Sabha Members can suggest the road works under PMGSY schemes in their given nodal districts,

(c) if so, whether directions have been issued in that connection;

(d) if not, the reasons therefor;

(e) whether any recommendation/suggestion of Rajya Sabha Members has been ignored in Karnataka;